

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS



Open Access, Refereed Journal Multi-Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions of the authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsoever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board



Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India. India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020). Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019



Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi. Formerly Assistant professor of Law, Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration. 10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.



Avinash Kumar



Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship. He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi. Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi. He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS
ISSN

2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

घरेलू हिंसा

लेखक - वर्षावती बघेल

1. दहेज क्या है
2. इसका इतिहास
3. कारक
4. दहेज प्रथा एक मुद्दा क्यों है
5. दहेज के खिलाफ कानून
6. दहेज प्रथा के खिलाफ आधार
7. निष्कर्ष

दहेज क्या है?

भारत में, दहेज की वैवाहिक प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। दहेज दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को धन का हस्तांतरण है। दहेज में पैसा, संपत्ति, गहने, वाहन, फर्नीचर, उपकरण, कपड़े और किसी भी प्रकार का उपहार शामिल है जिसे दिया जा सकता है या मांगा जा सकता है। [1]

दहेज प्रथा का इतिहास

दहेज सदियों से दिया जाता रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में कई संस्कृतियों में इसका प्रचलन है। यह मुख्य रूप से हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और जैनियों के बीच प्रचलित है। इसकी शुरुआत माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों को उनके आराम के लिए उपहार देने से हुई। जैसा कि मनु संहिता में लिखा गया है, दहेज उच्च जातियों द्वारा प्रचलित एक प्रतिष्ठित रूप था। प्राचीन काल में, राजा अपनी बेटियों को दहेज के साथ भेजते थे ताकि वे आराम से रह सकें। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो उन्होंने महिलाओं को किसी भी संपत्ति या धन के मालिक होने से रोक दिया, इस प्रकार उनका पूरा दहेज उनके पति और/या उनके ससुराल वालों के पास चला गया।

परंपरा

यह एक पारंपरिक प्रथा है जो कई सदियों से चली आ रही है। समय के साथ इसका महत्व और अभ्यास करने का कारण बदल गया है।

धार्मिक कारक

दहेज का महत्व भारत के कई धर्मों में मौजूद है।

हिन्दू धर्म

हिंदू धर्म में शादी के दौरान पिता कन्यादान करता है, जो बेटी को देने का कार्य है। कन्या का अर्थ है लड़की और दान का अर्थ है देना, इसलिए कन्यादान का अर्थ है बेटी का उपहार, इसलिए दहेज दूल्हे के लिए एक उपहार है क्योंकि वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले रहा है, इस प्रकार उसे संसाधन प्रदान कर रहा है।

सिख धर्म

सिख धर्म में दहेज को देहज कहा जाता है। इसकी शुरुआत आध्यात्मिक दहेज के रूप में हुई थी; इसका मतलब था कि जब कोई महिला अपना नया जीवन शुरू करती है तो उसे अपने साथ भगवान का नाम लेकर चलना चाहिए। हालाँकि, सामाजिक प्रभावों और लालच के प्रभाव के साथ, दहेज का महत्व बदल गया।

इसलाम

इस्लाम में, एक प्रकार का दहेज जिसे महर कहा जाता है, दूल्हे से दुल्हन को दिया जाता है। महर पति द्वारा अपनी पत्नी का सम्मान करने के लिए दिया जाता है और अब वह उसकी जिम्मेदारी लेता है।

“और औरतों को उनका मेहर अच्छे दिल से दो...” पवित्र कुरान

समय के साथ महर की अवधारणा बदल गई और जहाज़ बन गई। जहाज़ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह मुसलमानों, खासकर भारत में रहने वालों के बीच ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। जहाज़ दुल्हन द्वारा पति को दिया जाने वाला दहेज है। महर से जहाज़ में बदलाव कई सामाजिक कारकों के कारण हो सकता है। [7]

सामाजिक-आर्थिक कारक

कई मौकों पर माता-पिता अपनी बेटी की आर्थिक सुरक्षा के लिए दहेज देते हैं। हालाँकि दुल्हन का परिवार अच्छे इरादों से दहेज दे रहा है, लेकिन दूल्हा और उसका परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं। दहेज की उम्मीद होती है। शादी जोड़े की तुलना में माता-पिता के हितों पर अधिक तय की जाती है। माता-पिता आमतौर पर अपनी बेटियों की शादी उच्च स्थिति वाले परिवारों में करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, माता-पिता एक अमीर परिवार और एक शिक्षित दामाद की तलाश करते हैं, जिसके पास एक स्थिर नौकरी हो। शिक्षा के स्तर, नौकरी के शीर्षक और दूल्हे के लिए किसी भी भविष्य की संभावनाओं के साथ दहेज बढ़ता है। [8] [9]

दहेज प्रथा एक मुद्दा क्यों है?

पितृ सत्ता

दहेज प्रथा की परंपरा एक ऐसी चीज थी जो खुशी से और महिला के जीवन की बेहतरी के लिए दी जाती थी। लेकिन सदियों से यह महिलाओं का फायदा उठाने का एक तरीका बन गया है।

पितृ सत्ता की परिभाषा यह है कि जब समाज या सरकार में पुरुषों के पास वह शक्ति होती है जिससे महिलाओं को बाहर रखा जाता है। दहेज प्रथा में पितृसत्ता देखी जा सकती है, क्योंकि भले ही दहेज दुल्हन से और दुल्हन के लिए होता है, लेकिन दुल्हन को बाहर रखा जाता है और पुरुषों को शक्ति मिलती है। भारत में महिलाओं को यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि तलाक जैसा कोई विकल्प नहीं है; उनकी एकमात्र जिम्मेदारी विवाह को सफल बनाना है। यही कारण है कि कई महिलाएं दहेज की बढ़ती मांगों को पूरा करती हैं और कई दुर्व्यवहार का सामना करती हैं।

घरेलू हिंसा, दहेज हत्याएं और दुल्हन जलाना

दहेज के कारण कई महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। शेष या बढ़ा हुआ दहेज हड़पने के लिए महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा अंतहीन यातना देकर या तो मार दिया जाता है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार परिवार दूल्हे के परिवार द्वारा मांगे गए दहेज को देने में असमर्थ होते हैं। पति और ससुराल वाले दुल्हन के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करते हैं। दुल्हन उदास हो सकती है और खुद को मुक्त करने के लिए वह अंततः आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या के तरीके आत्मदाह, फांसी या जहर हैं। अगर उन्हें दहेज नहीं मिलता है और दुल्हन वापस लड़ती है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। दुल्हन को जलाना दुल्हन की हत्या करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधियों में से एक है। दुल्हन को जलाना तब होता है जब पति और/या ससुराल वाले दुल्हन को जला देते हैं और इसे एक दुर्घटना या आत्महत्या का रूप देते हैं। अन्य मामलों में, दुल्हन को फांसी पर लटका दिया जाता है या जहर दे दिया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि उसने आत्महत्या की है।

अन्य संघर्ष या अपराध

महिलाओं को दहेज की समस्या का सामना केवल विवाह के दौरान ही नहीं करना पड़ता, बल्कि महिलाएं और उनके परिवार वाले उनके जन्म से पहले ही दहेज की समस्या से जूझने लगते हैं।

लिंग चयनात्मक गर्भपात

भविष्य में दहेज से बचने के लिए माता-पिता लिंग आधारित गर्भपात करवाते हैं तथा कन्या भ्रूण का गर्भपात करा देते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या

सदियों से कई कारणों से नवजात लड़कियों की हत्या की जाती रही है। इसका एक मुख्य कारण भविष्य में दहेज से बचना है।

शिक्षा

बहुत सी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं। हालाँकि लड़कियों के शिक्षित न होने का एक बहुत ही आम कारण दहेज है। माता-पिता का मानना है कि शिक्षा पर उस पैसे को खर्च करने के बजाय, वे बाद में अपनी बेटी के लिए उच्च पद और शिक्षित पति ढूँढ सकते हैं। [10]

अध्ययनों से पता चलता है कि जब कोई महिला शिक्षित होती है, तो उच्च शिक्षित पुरुष को आकर्षित करने के लिए अधिक दहेज दिया जाता है। कई बार दूल्हे के परिवार को ऐसा लग सकता है कि अगर दुल्हन का करियर है तो वह घर के काम नहीं जानती या उसमें मदद नहीं करेगी, इसलिए उन्हें घर की देखभाल के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण हो सकता है कि कई परिवार अपनी बेटी को शिक्षित नहीं करते हैं, इसके बजाय वे उस पैसे को दहेज के लिए बचाते हैं। [10]

दहेज के खिलाफ कानून

भारतीय न्याय संहिता 2023

BNS Section 85 एक आपराधिक कानून है इस कानून में कहा गया है कि दहेज वसूलने के लिए किसी महिला के साथ क्रूरता करने पर तीन या उससे अधिक साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी।

Section 80 दहेज हत्या करने पर 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास तक कि हो सकेगी

दहेज निषेध अधिनियम 1961

1961 के अधिनियम ने कई राज्यों में दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दहेज देने या लेने वाले किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। इस दंड में कम से कम पांच साल की कैद और पंद्रह हजार रुपये से कम या दहेज की राशि के बराबर जुर्माना शामिल है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी राशि अधिक है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम [14] पारित किया गया था। यह कानून दहेज के मामलों में मदद करता है क्योंकि कई बार घरेलू हिंसा का कारण दहेज का भुगतान न किया जाना होता है। यह अधिनियम एक नागरिक कानून है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्तियों को अपराधी बनाने या दंडित करने के लिए निर्धारित नहीं है, हालाँकि यह महिलाओं को उनके पति और/या ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले घरेलू दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है।

दहेज प्रथा के खिलाफ़ आधार

दहेज और दुल्हन जलाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी

1993 में श्री हिमेंद्र ठाकुर द्वारा स्थापित, इसका मुख्य लक्ष्य जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना, पीड़ितों को सहायता (चिकित्सा, भावनात्मक, वित्तीय) प्रदान करना और दहेज देने से बचने में मदद करना है। दहेज और दहेज हत्याओं को खत्म करने के लिए उनके पास छह सूत्री कार्यक्रम है। वे पीड़ितों को अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि नौकरी खोजने और स्वतंत्र होने के लिए नौकरी केंद्र बनाना।

अन्य दहेज विरोधी संस्थाएं और समूह

इनमें से कई संस्थाएं और समूह स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने और दहेज से संबंधित लोगों की नकारात्मक धारणा को बदलने के लिए काम करते हैं।

ऐतिहासिक निर्णय

हालांकि दहेज हत्या से संबंधित पूरी बात और कानूनों को ठीक से लागू कर पाना मुश्किल रहा है, फिर भी कुछ ऐसे कारण थे, जिन्होंने मौजूदा दोषों की पृष्ठभूमि में एक सफलता दिलाई।

सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 304-बी के तत्वों को स्थापित कर सकता है, तो निर्दोषता साबित करने का भार पूरी तरह से बचाव पक्ष पर है। उसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए की तुलना में कहीं अधिक कठोर है इस अर्थ में कि इसके तहत अपराध संज्ञेय, गैर – जमानती हैं और सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

जबकि **मुस्तफा शहादल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012)** के मामले में, अदालत के निर्णय के अनुसार धारा 304-बी के तहत इस्तेमाल की गई भाषा, “मृत्यु से तुरंत पहले” भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत किसी निश्चित समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं करती है। तदनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा “मृत्यु से तुरंत पहले” शब्द निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, इसका तात्पर्य यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्रुगत मृत्यु के बीच अंतराल बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय में दूर की है और संबंधित महिला के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त पुरानी हो गई है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

निष्कर्ष

महिलाओं को समाज की रीढ़ माना जाता है और दहेज के लिए उन्हें मारना या जला देना अपने आप में एक शर्मनाक कृत्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ प्रावधान और उपाय करने चाहिए, जिनमें सबसे

प्रमुख है महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखना ताकि वे उन पर निर्भर न रहें और महिला आरक्षण को महिला सशक्तिकरण का स्रोत बनाना। छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए हमें दहेज के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। क्या यह बिल्कुल विरोधाभासी नहीं है कि जिस देश में विवाह को पवित्र माना जाता है, वहां चंद पैसों के लिए महिलाओं को लोगों के हाथों जला दिया जाता है। दहेज पर रोक लगनी चाहिए।

